



राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रकाशोत्सव के पावन पर्व दीपावली पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों की खुशहाली की कामना की।

अन्तिम समय में महाराष्ट्र में प्रत्याशी बदल रही हैं भाजपा व कांग्रेस

भाजपा ने 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे, कांग्रेस ने पांच के

■ महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि, कुछ क्षेत्रों में कुछ दलों ने कई उम्मीदवारों के नामांकन दिये हैं।

मुंबई, 30 अक्टूबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बीत जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भाजपा ने आठ मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस ने पांच को टिकट नहीं दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दो गुट, एक अजित पवार के नेतृत्व में और दूसरा उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व में, ने दो मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने हाल ही में विद्रोह के दौरान शिंदे का समर्थन करने वाले अपने लगभग सभी विधायकों को रखने का फैसला किया है, लेकिन एक को छोड़कर।

सत्तारूढ़ महागठबंधन (महायुति) और विपक्ष (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी) के उम्मीदवारों की सही संख्या स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुछ दलों ने कुछ क्षेत्रों में कई

तेलंगाना ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "टी.पी.सी.सी. ने 2025 में जनगणना करने के भारत सरकार के फैसले का संज्ञान लिया। टी.पी.सी.सी. ने भारत सरकार से यह मांग करने का प्रस्ताव पारित किया कि आगामी दशकीय जनगणना में ओ.बी.सी. जातीय जनगणना को शामिल किया जाए इस संबंध में भारत सरकार को तत्काल आदेश जारी करना चाहिए।"

मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में जातीय जनगणना करने की वकालत की थी और आबादी के अनुपात में संसाधनों के बंटवारे का विचार रखा था। महेश कुमार गौड़ ने राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराने के लिए कांग्रेस सरकार की सराहना की।

कैनडा ने अचानक इतना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को खूब कोशिशें कर लीं तथा इस संबंध में भारत को विभिन्न प्रलोभन भी दिये गये। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद, भारत, रूस के साथ दोस्ती जारी रखने की अपनी नीति पर कायम रहा है। भारत ने अभी पिछले सप्ताह ही ब्रिक्स सम्मेलन के अवसर पर रूसी राष्ट्रपति के साथ विचार-विमर्श एवं दोस्ताना बातचीत की थी। भारत ने चीन के साथ हिमालयी सीमाओं पर अपने मतभेदों को लेकर, चीन के साथ एक प्रकार का समझौता किया है। हालांकि, समझौते का जो रूप सामने आया, उससे सारे मुद्दों का समापन नहीं हो रहा, फिर भी दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये हैं कि सीमा पर आमने-सामने खड़ी दोनों देशों की सेनाओं हटा लेने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाये। यह एक नया घटनाक्रम है, जो भारत को रूस-चीन युग के साथ खड़ा करता है तथा

रूस-चीन युग पश्चिमी प्रभुत्व दुनिया पर पश्चिमी दबदबे के जारी रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा एवं संकट है। पृष्ठभूमि में कुछ भी रही हो, लेकिन कैनडा के ये भड़काने वाले बयान भारत

‘कैनडा में ...

बनती है कि इससे अन्य अपराधों का होना आसान हो जायेगा, जिन अपराधों में इस अपराधी तथा उसके सहयोगियों द्वारा की जाने वाली लूट-खसोटी भी शामिल है। कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुडो द्वारा सिक्ख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की लिप्तता के बारे में आरोप लगाये जाने के बाद, इस बिन्दु को लेकर भारत-कैनडा सम्बन्धों में कड़वाहट तो आ गई थी, लेकिन यह पहला अवसर है, जब कैनडा ने भारतीय गृह मंत्री की लिप्तता को लेकर, उन पर सीधा आरोप लगाया है। "रॉयल कैनैडियन माउन्टेड पुलिस" जो कैनडा में भारतीय कार्यवाहियों की जाँच-पड़ताल कर रही है, ने अभी तक सार्वजनिक रूप से अमित शाह पर आरोप लगाया है। जब कैनडा सरकार ने डिप्लोमैटिक वेबर के तहत, भारत के छः राजनयिकों, जिनमें पूर्व हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा भी शामिल थे, को निज्जर की हत्या में "पर्सन ऑफ इन्ट्रेस्ट" मानते हुये भारत वापस भेज दिया था, उसके बाद दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक गतिरोध काफी बढ़ गया है।

और पश्चिमी गठबंधन के बीच के रिश्तों को खराब कर रहे हैं। इन घटनाक्रमों के बाद, पश्चिमी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों के बारे सजग रहना होगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्षों से वृद्धि नहीं हुई थी। निवर्तमान शिरोर सरकार ने वेतन वृद्धि का समर्थन किया कंपनियों से वेतन बढ़ाने को कहा। यह भी जापान की अर्थव्यवस्था में बदलाव का एक अंग था। जापान ने आजीवन रोजगार की संस्कृति देखी है। लोग जब कोई काम या नौकरी करते थे तो आजीवन वही काम करते थे। पर हाल ही में यह चलन बदल रहा है। युवा वर्ग नौकरी भी बदल रहे हैं और ज्यादा वेतन के लिए सौदेबाजी भी कर रहे हैं। शिरोरु सरकार ने भी इस विचार का समर्थन किया उन्होंने वेतन बढ़ाने और रोजगार प्रदाताओं में टैलेंट के लिए प्रतिस्पर्धा का समर्थन किया

शौचालय में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) यात्रा कर रहे हैं, जबकि शेष अनारक्षित साधारण श्रेणी के गरीब यात्री हैं।

सूत्रों ने कहा कि रेलवे ने राजधानी क्षेत्र के स्टेशनों पर कम से कम एक होल्डिंग एरिया बनाया है। इसमें साधारण श्रेणी के यात्रियों को रोका जाता है। उनके भोजन एवं पानी का इंतजाम भी किया जा रहा है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगने एवं गेट खुलने के बाद उतनी ही संख्या में यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, जितने गाड़ी में सवार हो सकें। बाकी यात्रियों को दूसरी गाड़ी में सवार कराया जाता है। इतना ही नहीं, रेलवे के अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि यात्री शौचालय में पाये जाते हैं तो गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा। यात्रियों के शौचालय के खाली करने पर ही गाड़ी को चलने का सिग्नल दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि दीपावली के दिन गुरुवार 31 अक्टूबर को रेलवे पूर्वी भारत के विभिन्न स्थानों के लिए 164 और अगले दिन शुक्रवार एक नवंबर को 167 विशेष गाड़ियों का परिचालन करेगा।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हासिल हो गया था। यह स्थिति बदल गई और इस वर्ष अक्टूबर में इनफ्लेसन रेट 3 प्रतिशत हो गई। इसका स्वागत किया जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में इसका विरोध हुआ लोगों ने कीमते बढ़ने का विरोध किया क्योंकि उन्होंने कभी महंगाई नहीं देखी थी। दूसरे जापान में वेतन की दरें स्थिर रही उसमें वर्षों से वृद्धि नहीं हुई थी। निवर्तमान शिरोर सरकार ने वेतन वृद्धि का समर्थन किया कंपनियों से वेतन बढ़ाने को कहा। यह भी जापान की अर्थव्यवस्था में बदलाव का एक अंग था। जापान ने आजीवन रोजगार की संस्कृति देखी है। लोग जब कोई काम या नौकरी करते थे तो आजीवन वही काम करते थे। पर हाल ही में यह चलन बदल रहा है। युवा वर्ग नौकरी भी बदल रहे हैं और ज्यादा वेतन के लिए सौदेबाजी भी कर रहे हैं। शिरोरु सरकार ने भी इस विचार का समर्थन किया उन्होंने वेतन बढ़ाने और रोजगार प्रदाताओं में टैलेंट के लिए प्रतिस्पर्धा का समर्थन किया

कैलादेवी से लौट रहे आगरा के एक दम्पति की हत्या

सुबह 8 बजे पति-पत्नी का शव कार में लहलूहान हालत में मिला

करौली, 30 अक्टूबर (नि.स.)। करौली जिले में कैलामाता के दर्शन कर लौट रहे पति-पत्नी की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। बुधवार प्रातः 8:00 बजे ग्रामीणों को दोनों के शव कार में लहलूहान हालत में मिले। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी

मामला मासलपुर थाना इलाके के भोजपुर गांव का है। कार में मिली आई.डी. से दोनों की पहचान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सांथा किरावली निवासी विकास (22) पुत्र जितेंद्र और दीक्षा (18) पुत्री सियाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के शव करौली जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाए और परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार जनों के सुपुर्द कर दिये।

बताया जा रहा है कि मृतक विकास और दीक्षा कि 9 महीने पहले शादी हुई थी। करौली पुलिस

■ विकास और दीक्षा की शादी 9 माह पूर्व ही हुई थी। वे कैलादेवी दर्शन कर लौट रहे थे। दोनों के शरीर पर गोलीयों के निशान तथा कार में कारतूस के खोखे मिले।

उपाधीक्षक अनुज शुभम ने बताया कि बुधवार प्रातः करीब 8:00 बजे भोजपुर के पास एक कार में पुरुष और महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची मासलपुर थाना पुलिस ने देखा कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गई थी। शरीर पर गोलीयों के निशान थे। कार और घटना स्थल पर कारतूस के खोखे पड़े मिले हैं। कार में मिली आईडी से पता चला कि विकास और दीक्षा पति-पत्नी थे।

हादसे की सूचना पर करौली पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने एफ.एस.एल. टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। कार को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया, विकास के दो गोली लगीं जबकि, दीक्षा को लेकर सभी एंगल से जांच कर रही है। मृतका के पिता ने बताया कि कार में कुछ लोग साथ थे।

विकास और दीक्षा मंगलवार दोपहर 1:00 बजे कैलादेवी के लिए निकले थे।

दीक्षा के पिता सियाराम ने बताया कि मंगलवार शाम चार बजे दीक्षा से बात हुई थी, तब सब ठीक था। वे कैलादेवी से दर्शन कर लौट रहे थे। उनकी शादी करीब 9 महीने पहले हुई थी। सियाराम ने बताया कि कुछ और लोगों के भी विकास और दीक्षा के साथ कार में आने की सूचना थी।

इजरायल ने हिजबुल्लाह के नये चीफ को धमकी दी

तेल अवीव, 30 अक्टूबर। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला, तो वह हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा।

इजराइल के रक्षा मंत्री अब गैलेंट ने कासिम की नियुक्त पर चेतावनी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर

■ इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि नया चीफ कासिम सबसे कम दिन चीफ रहेगा।

कासिम की फोटो पोस्ट के साथ लिखा, "अस्थायी नियुक्ति ज्यादा समय तक नहीं चलेगी।"

इजराइली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद मंगलवार को हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ चुना था। कासिम हिजबुल्लाह में इससे पहले नंबर 2 की पॉजिशन पर था। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। यू.ए.ई. के मीडिया हाउस इरेम न्यूज के मुताबिक वह अभी ईरान में है।

कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरुत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नेताओं ने इजराइल के हमले के डर से कासिम को ईरान बुलाया था। कासिम संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहा है और इजराइल के साथ संघर्ष में अक्सर प्रवक्ता की भूमिका निभाता रहा है। इजराइल का कहना है कि लेबनान में शांति केवल तभी ही आएगी, जब हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति खत्म कर दी जाए।

25.75 लाख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बैठकर जटबाड़ा से मोहनपुरा जा रहा था। इस दौरान पंचमुखी मंदिर के पास से कार चालक ने तेज गति और लापरवाही से कार को चलाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर और अन्य जगहों पर गंभीर चोट आई। इस कारण वह चलने-फिरने और वजनी काम करने में असमर्थ हो गया। इसलिए उसे 25.75 लाख रुपए का क्लेम दिलाया जाए।

जवाब में बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि दुर्घटना की रिपोर्ट एक्सीडेंट के 23 दिन बाद दर्ज कराई गई है और इसमें देरी का उचित कारण भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा क्लेम के लिए वाहन स्वामी और पुलिस से मिलीभगत कर झूठे साक्ष्य पेश किए गए हैं। एक और मोटरसाइकिल पर पीछे से टक्कर मारने की बात कही गई है, लेकिन दूसरी ओर मोटरसाइकिल के पीछे कोई डैमेज नहीं है। इसलिए क्लेम याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने क्लेम याचिका को खारिज कर दिया है।

प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली पर अयोध्या जगमगाया

योगी आदित्यनाथ ने पहला दिया जलाया, 55 घाटों पर 25 लाख दिये जलाये गये

अयोध्या, 30 अक्टूबर। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या की दिवाली इस बार बेहद विशेष है क्योंकि राम मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। अयोध्या दुल्हन की तरह शब चुकी है। चप्पा-चप्पा जगमगा रहा है। बुधवार को राम मंदिर और सरयू तट पर दीपोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहला दीया जलाकर इसकी शुरुआत की। सरयू नदी के 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीये जलाए गए। कुल 28 लाख दीयों का इंतजाम किया गया था। ताकि दीपोत्सव के लिए दीयों की कमी न हो जाए।

अयोध्या में आज एक साथ दो रिवांई बने। पहला रिवांई सबसे ज्यादा दीये जलाने का बना। दीपोत्सव में कुल 25 लाख 12 हजार 585 दीये जलाए गए। पिछले साल 22 लाख दीये जलाए गए थे। इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिवांई में दर्ज किया गया। दूसरा रिवांई सरयू तट पर एक साथ 1121 लोगों के आरती करने का है। यह भी विश्व रिवांई है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने

रिवांई बने। पहला रिवांई सबसे ज्यादा दीये जलाने का बना। दीपोत्सव में कुल 25 लाख 12 हजार 585 दीये जलाए गए। पिछले साल 22 लाख दीये जलाए गए थे। इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिवांई में दर्ज किया गया। दूसरा रिवांई सरयू तट पर एक साथ 1121 लोगों के आरती करने का है। यह भी विश्व रिवांई है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने

लद्दाख में सेना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटनी शुरू हुई थी। डेमचोक और देपसांग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए। बख्तरबंद गाड़ियों और मिलिट्री डिवाइसेस भी पीछे ले जाए गए। पहले दिन 50 से 50 प्रतिशत डिस्पोजमेंट हुआ। इसके बाद मंगलवार तक 90 प्रतिशत डिस्पोजमेंट पूरा हो चुका था। बुधवार को देपसांग और डेमचोक पर डिस्पोजमेंट का काम पूरा हो गया।

लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने न्यायिक कार्यों में भाग नहीं लिया

गाज़ियाबाद के वकील, जिला जज व पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं

देवरिया, 30 अक्टूबर। गाजियाबाद में मंगलवार को जिला जज की अदालत में वकीलों और जज के बीच नोकझोंक तथा उसके बाद वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को यहाँ वकीलों ने प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से विरत रहे।

सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी ने बताया कि गाजियाबाद कचहरी में जिस तरह से वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया। वह बहुत ही निन्दनीय है और इसी से

■ दूसरी ओर पुलिस ने बार के पूर्व अध्यक्ष सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की।

आक्रोशित अधिवक्ता एक मीटिंग कर अपना विरोध प्रकट करते हुए न्यायिक कार्य से विरत हैं। वकील दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में पुलिस ने बार के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव समेत 50 अज्ञात वकीलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। जिससे देवरिया सहित प्रदेश के सारे वकील आक्रोशित हैं।

वकीलों की मांग है कि गाजियाबाद के जिला जज का स्थानांतरण और निलंबन, वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और घायल वकीलों को दो-दो लाख रूपये की कीमत पर अपने घर भर रहे थे। और पैसा बटोर रहे थे। सत्तारूढ़ दल ने राजनैतिक फंडिंग बढ़ा दी, लेकिन यह चीज सामने आई कि इन फंड्स का कुछ हिस्सा कानून-निर्माताओं की तिजोरियों में पहुंच रहा था। इन घोर अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा हुई। प्रधानमंत्री की टालमटोल से भी अनिश्चितता की भावना जनता तक पहुंची। यहां तक कि, कुछ सामान्य तथा निर्दोष लगने वाले मुद्दों भी लोगों में चिढ़ पैदा करने लगे, जबकि सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने इस बिन्दु को लेकर भी चर्चा छेड़ दी कि महिलाओं को शादी के बाद भी, अपना शादी से पहले वाला सपनेम ही रखने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन उन्हें अपने इंसानों से पीछे हटना पड़ा तथा कहना पड़ा कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। सुरक्षा मामलों में भी, प्रधानमंत्री इतने ही अनिश्चित किन्तु दृढ़ बने रहे। रक्षा मंत्री के रूप में, मैं

की सहायता दी जाय। बार कार्डिनल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है।

बार कार्डिनल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवकुमार गौड़ ने गाजियाबाद मामले में विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने पूरे क्लेम की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई है। उन्होंने पूरे मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट बार कार्डिनल में पेश करने के निर्देश कमेटी को निर्देश दिए गए हैं।

राजनैतिक अनिश्चितता से जूझ रहा ...

इसके पीछे आईडिया यह था कि वेतन बढ़ने और मूल्य वृद्धि से उपभोक्ता बचत करने की बजाय अपनी आय खर्च करना शुरू करेंगे। बचत की बजाय खर्च करने से प्रोथ और विकास में वृद्धि होती है।

जापानी अर्थव्यवस्था की अंतिम खासियत रही बढ़ता सार्वजनिक कर्ज और उस पर बढ़ता ब्याज। जापान का सार्वजनिक कर्ज देश की जीडीपी से भी काफी अधिक है। सरकार इस बात को जानती है, और इससे निपटने पर विचार कर रही है। एक तरीका है टैक्स बढ़ाया जाए। वस्तुओं की खपत पर टैक्स लगाने के साथ-साथ बिक्री का भी प्रस्ताव किया गया। लेकिन इन कदमों का भारी विरोध किया गया। वस्तुतः जापानी संघीय सरकार मुश्किल में फंस गई है। इन आर्थिक बुराइयों का प्रतिकार करने के उसके प्रयासों से नाराजगी पैदा हो रही है।

इनके साथ ही, निजी लाभ के लिए राजनैतिक भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ। असल में, ऐसा हुआ था। जब कीमते बढ़ रही थीं तथा सार्वजनिक वित्त ऋण के बोझ से चरमरा रहा था, राजनेताओं

की कीमत पर अपने घर भर रहे थे। और पैसा बटोर रहे थे। सत्तारूढ़ दल ने राजनैतिक फंडिंग बढ़ा दी, लेकिन यह चीज सामने आई कि इन फंड्स का कुछ हिस्सा कानून-निर्माताओं की तिजोरियों में पहुंच रहा था। इन घोर अनियमितताओं की जानकारी मिलने पर, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया पैदा हुई। प्रधानमंत्री की टालमटोल से भी अनिश्चितता की भावना जनता तक पहुंची। यहां तक कि, कुछ सामान्य तथा निर्दोष लगने वाले मुद्दों भी लोगों में चिढ़ पैदा करने लगे, जबकि सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने इस बिन्दु को लेकर भी चर्चा छेड़ दी कि महिलाओं को शादी के बाद भी, अपना शादी से पहले वाला सपनेम ही रखने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन उन्हें अपने इंसानों से पीछे हटना पड़ा तथा कहना पड़ा कि इस मुद्दे पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है। सुरक्षा मामलों में भी, प्रधानमंत्री इतने ही अनिश्चित किन्तु दृढ़ बने रहे। रक्षा मंत्री के रूप में, मैं

शिरोरु ने मजबूत तथा दृढ़ जापान का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने यहां तक कहा था कि पश्चिमी गठबंधन "नाटो" के समकक्ष एशियाई गठबंधन बनाया जायेगा।

लेकिन उनके इस विचार को अमेरिका का समर्थन नहीं मिला तथा इसलिए, यह विचार एकाएक छोड़ दिया गया। जापानी सुरक्षा बलों तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के विचार पर भी आगे वांछित ध्यान नहीं दिया गया, फलितो अप नहीं हुआ।

फिर भी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की बात खारिज कर दी है। वे, जैसे भी हो, एक नया गठबंधन बनाने तथा गठबंधन सरकार चलाने का आशा संजोये हुए हैं। इससे उन पर बहुत बोझ पड़ जायेगा। उनके अन्य साथी भी इससे कुछ काम लेने के बारे में सोच रहे हैं। जापान की बात यह है कि जापान में फिलहाल राजनैतिक अनिश्चितता की स्थिति रहेगी लेकिन विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं, कहीं जायेगी।